

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 33 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

हरखूदेवी पत्नी पदमाराम बनाम 1.आदूराम पुत्र खेमाराम वगै.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 34 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

हरखूदेवी पत्नी पदमाराम बनाम 1.आदूराम पुत्र खेमाराम वगै.

अपीलांत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोंडेंट की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:- 23.11.2021

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 को अपीलांत व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी की गई। अपीलांत को कैम्प कोर्ट के बारे में कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई इस कारण अपीलांत को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी तथा तहसीलदार शिव ने अपीलांत को सूचना दिये बिना ही एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर कैम्प कोर्ट नागड़दा में दिनांक 22.06.2016 को पेश कर दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विभाजन प्रस्ताव पर सुने बिना दिनांक 22.06.2016 को दूसरे गांव कैम्प कोर्ट नागड़दा में अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया। वर्तमान में उतरदातागण द्वारा अपीलांत के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांत को जबरन बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा कहा कि हमने कोर्ट से काफी समय पूर्व निर्णय करवाकर भूमि का बंटवाड़ा करवा लिया है तथा अब मौके पर राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार काबिज होंगे, जिस पर अपीलांत को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांत ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त की तो अपीलांत को सर्वप्रथम अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान



राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RLW 2006(1) Page 324

AIR 2005 SC Page 1158

DNJ 2009 SC Page 846

RRT 2021(1) Page 482

RRT 2008(2) Page 1406

अधिवक्ता रैस्पोंडेंट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जबाव पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध दिनांक 13.04.2018 को यानि तकरीबन 01 वर्ष 10 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलांट के पति पदमाराम दिनांक 25.05.2016 को कैम्प काश्मीर कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने बाबत सहमति दी थी जिसका आदेशिका में अपीलांट के पति के हस्ताक्षर है। इस कारण अगली सुनवाई तारीख नागड़दा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने की पूर्ण जानकारी हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की

अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 अपीलांट अधिवक्ता एवं अपीलांट के पति श्री पदमाराम की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट द्वारा



राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जायपुर

प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष 10 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।



(अरविन्द कुमार सिन्हा)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार सिन्हा)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर